मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक- 09.10.2012 को राज्य में जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति की समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

(1) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार
(2) प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार
(3) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार
(4) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम
(6) प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रोन, पटना
(7) उपमहाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (क्षेत्र), पटना
(8) राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना ।

"

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई । प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई कि कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत राशन कार्ड डिजिटाईजेशन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारत समय सीमा 31.10.2012 तक निर्धारित है । जन वितरण प्रणाली दुकानों की इन्ट्री का कार्य जिलों द्वारा लगभग पूरा किया जा चुका है । राशन कार्ड इन्ट्री हेतु 12 जिलों का Set-up file NIC के द्वारा बेल्ट्रॉन को उपलब्ध कराया जा चुका है । 5 जिलों के Set-up file बेल्ट्रॉन को उपलब्ध कराने हेतु NIC को निदेशित किया गया है । शेष 21 जिलों से जन वितरण प्रणाली दुकानों की इन्ट्री का कार्य पूर्ण होने की सूचना प्राप्त की जा रही है । उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् इन 21 जिलों के Set-up file बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करा दिये जाएंगे । राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुछ जिलों से वर्तमान डाटावेस में अतिरिक्त राजस्व ग्राम जोडने का अनुरोध किया गया है जिसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई है । मुख्य सचिव द्वारा दिनांक- 15.10.2012 को होनेवाले अगले वीडियो कॉनफ्रेंसिंग से पूर्व हर हाल में सभी जिलों से जन वितरण प्रणाली दुकानों की इन्ट्री का कार्य पूर्ण होने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर लेने हेतु निदेशित किया गया ।

2. राशन कार्ड इन्ट्री की समीक्षा के क्रम में प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन द्वारा यह जानकारी दी गई कि 6-7 जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों से लगभग 40 लाख राशन कार्ड धारकों से संबंधित डाटा बेल्ट्रॉन द्वारा चयनित वेन्डरों द्वारा प्राप्त कर ली गई है । मुख्य सचिव द्वारा जिलावार राशन कार्ड डाटा की प्राप्ति की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया गया । उनके द्वारा प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को निदेशित किया गया कि जिलावार/प्रखंडवार पंचायत/वार्ड की संख्या तथा कितने पंचायत/वार्ड से राशन कार्ड इन्ट्री हेतु डाटा प्राप्त हुए हैं एवं कितने पंचायत/वार्ड में लंबित हैं, इससे संबंधित प्रतिवेदन आज हीं उपलब्ध कराया जाय ।

3. मुख्य सचिव द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि दिनांक- 15.11.2012 तक सभी पंचायतों से संबंधित डाटावेस बेल्ट्रॉन द्वारा चयनित वेंडरों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय । उक्त तिथि तक जिस प्रखंड का डाटा वेंडरों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा उन प्रखंडों के संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय ।

4. मुख्य सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को निदेशित किया गया कि प्रथम चरण में राशन कार्ड इन्ट्री हेतु प्राप्त डाटावेस की इन्ट्री का कार्य दिनांक- 31.12.2012 तक पूर्ण कर लिया जाय एवं आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर पूर्णतः शुद्ध डाटावेस अन्तिम रूप से दिनांक- 15.01.2013 तक तैयार करा लिया जाय ।

5. समीक्षा के क्रम में एन0आई0सी0 द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य स्तर पर तैयार कराये जा रहे डाटावेस को नई दिल्ली स्थित डाटा सेंटर में संरक्षित रखा जाएगा । मुख्य सचिव द्वारा एन0आई0सी0 को निदेशित किया गया कि उक्त डाटावेस को access करने की सुविधा सभी के लिए हो ऐसी व्यवस्था की जाय ।

6. पी0डी0एस0 कम्प्यूटराईजेशन के अगले चरण में Supply Chain Management का कार्यान्वयन किया जाना है जिसमें बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की सबसे प्रमुख भूमिका है । मुख्य सचिव द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया । प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निगम में कर्मियों के अभाव के कारण कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन में कठिनाई होगी । मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि निगम किसी एजेंसी जो निगम को योग्य कर्मी उपलब्ध करा सके, को सेवा-प्रदाता के रूप में चयनित कर इस दिशा में कार्य कर सकती है । मुख्य सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक को निदेशित किया गया कि भारतीय खाद्य निगम में कम्प्यूटरीकरण से संबंधित जानकारी भी प्राप्त करते हुए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में कम्प्यूटरीकरण की स्थिति के संदर्भ में दो सप्ताह में वस्तुस्थिति प्रतिवेदित किया जाय ।

7. मुख्य सचिव द्वारा यह निदेशित किया गया कि जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की जाय एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न चरणों में किये जाने वाले कार्यों को ससमय पूर्ण किया जाय ।

8. मुख्य सचिव द्वारा पी0डी0एस0 कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति की समीक्षा हेतु पुनः दिनांक- 25.10.2012 को बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया ।

ह0/-
मुख्य सचिव,
बिहार ।

ज्ञापांक- प्र07-बैठक-04/2011 6614 खाद्य, पटना/दिनांक- 12/10/2012

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (क्षेत्र), पटना/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रोन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला सूचना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(जयशंकर प्रसाद यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

D:\Year-2012\Sec-7\PDS Computerization.doc